ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2022; 8(6): 29-31
www.allresearchjournal.com
Received: 25-02-2022
Accepted: 16-04-2022

प्रेम परिहार
सहायक आचार्य, ईएएफएम, राजकीय बांगड स्नातकोत्तर महाविद्यालय डीडवाना, नागौर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author:
प्रेम परिहार
सहायक आचार्य, ईएएफएम, राजकीय बांगड स्नातकोत्तर महाविद्यालय डीडवाना, नागौर, राजस्थान, भारत

डिजिटल करेंसी : एक नवीन अवधारणा

प्रेम परिहार

सारांश
विश्व में क्रिप्टो मुद्रा के बढ़ते प्रचलन को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी बजट 2022–23 में डिजिटल मुद्रा के रूप में डिजिटल रूपया जारी करने की घोषणा की है। डिजिटल मुद्रा को कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट आदि तकनीकों से उपयोग में लाया जाएगा। डिजिटल मुद्रा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के रूप में होगी। इस मुद्रा का नाम डिजिटल रूपया (Digital Rupee) होगा। इस मुद्रा को आभासी मुद्रा के रूप में भी जाना जा सकेगा क्योंकि इसे देखा या छुआ नहीं जा सकेगा और न ही जेब या पर्स में रखा जा सकेगा। इस मुद्रा (करेंसी) को भारतीय रिज़र्व बैंक जारी करेगा। यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी। इस प्रकार की मुद्रा के कई लाभ है जैसे कि इससे नकदी पर निर्भरता कम होगी। इससे कागजी मुद्रा की छपाई, भण्डारण और परिवहन की लागतों में कमी होगी। साथ ही देश के संसाधनों की बचत भी होगी। इससे कम समय एवं कम लागत में भुगतान हो सकेगा। परन्तु इसके नियमन एवं नियंत्रण हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक को वैधानिक उपायों एवं दण्डों की आवश्यकता होगी। सरकार को भी सचेत रहने की आवश्यकता है ताकि इसके दुरूपयोग से बचा जा सके।

कूटशब्द : डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी

प्रस्तावना
देश में डिजिटलीकरण की बयार चल रही है। बैंकों, शिक्षा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सरकारी कार्यालयों आदि में कार्य डिजिटलीकरण के माध्यम से किया जा रहा है। बैंक और भुगतान संबंधी कार्यों में कुछ हद तक जनसामान्य भी जागरूक हुआ है। परन्तु डिजिटलीकरण और डिजिटल मुद्रा में बहुत अंतर है। डिजिटलीकरण में भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों के माध्यम से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरूआत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और इंटर बैंक भुगतान प्रणाली से हुई। इससे बैंकिंग कुशलता में वृद्धि होती है परन्तु देश की बुनियादी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। जबकि डिजिटल मुद्रा ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी आधारित मुद्रा है जो देश की मुद्रा मात्रा को प्रभावित करेगी। भारत के बजट 2022–23 में डिजिटल मुद्रा के रूप में डिजिटल रूपया जारी करने की घोषणा की है। इस मुद्रा को नए वित्त वर्ष में लागू किया जाना है। किसी भी मुद्रा को मुद्रा तब माना जाता है जबकि उसे देश के केंद्रीय बैंक ने सरकार के द्वारा निश्चित विधान द्वारा जारी किया गया हो। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा डिजिटल मुद्रा को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। डिजिटल मुद्रा को कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट आदि तकनीकों से उपयोग में लाया जाएगा। कई देशों में डिजिटल मुद्रा को डिजिटल मनी या साइबर कैश के नाम से भी जाना जाता है।

अध्ययन के उद्देश्य
1. डिजिटल मुद्रा की अवधारणा को जानना।
2. डिजिटल मुद्रा की कार्यविधि को जानना।
3. डिजिटल मुद्रा की आवश्यकता के कारणों को जानना।
4. डिजिटल मुद्रा का भविष्य जानना।
5. डिजिटल मुद्रा एवं क्रिप्टो मुद्रा के मध्य अंतर को जानना।

शोध विधि
प्रस्तुत शोध पत्र विवरणात्मक शोध विधि से लिखा गया है। शोध पत्र लिखने में द्वितियक स्रोतों का प्रयोग किया गया है। इस हेतु तथ्यों का संकलन विभिन्न पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, पुस्तकों एवं इन्टरनेट के माध्यम से किया गया है।

शोध समीक्षा

गुप्ता अजय 2022 ने अपने लेख में बताया है कि डिजिटल मुद्रा नगदी मुद्रा का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है। जिसे भारत सरकार द्वारा मान्यता होगी। यह दो प्रकार की होगी। पहली खुदरा जिसे आम आदमी प्रयोग करेगा और दूसरी थोक जिसे वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रयोग में लाया जाएगा। इस मुद्रा को सॉवरेन मुद्रा (Sovereign Currency) यानि उस देश की मुद्रा में बदला जा सकता है। जबकि क्रिप्टो मुद्रा में इस तरह की सुविधा नहीं होती है, यह एक तरह से निजी मुद्रा है।

नीरज सिंह 2022 ने भास्कर एक्सप्लेनर में बताया है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में दिसंबर 2021 तक 87 देश शोध कर रहे थे। इन देशों का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 90 प्रतिशत से अधिक की भागीदारी है। इनमें से 35 देश तो वर्ष 2022 को लागू करने का विचार रखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में वेतन का 50 प्रतिशत डिजिटल मुद्रा के रूप में मिलता है। विश्व बैंक के अनुसार अभी दूसरे देशों में मुद्रा भेजने पर 7 प्रतिशत का शुल्क भुगतान किया जाता है जो डिजिटल मुद्रा के आने पर 5 प्रतिशत ही रह जाएगा। इससे कम आय वाले देशों को प्रतिवर्ष 1.2 लाख करोड़ रूपए का लाभ होगा।

मुद्रा का विकास

सामान्य अर्थों में मुद्रा का मतलब पैसे या धन के उस रूप से लगाया जाता है जिससे दैनिक जीवन में क्रय–विक्रय का कार्य किया जाता है। सबसे पहले वस्तु विनिमय की व्यवस्था थी जो औद्योगिक युग में धातुओं की खोज के कारण धातु मुद्रा का प्रचलन हुआ। ऐसा माना जाता है कि भारत उन प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जहाँ सबसे पहले मुद्रा प्रचलन में आई। 2600 साल पहले भी मुद्रा का प्रचलन था। प्राचीन मुद्रा के बारे में जाने तो ज्ञात होता है कि प्राचीनकाल में तीन फूटी कौडी एक कौडी के बराबर होती थी। 10 कौडी एक दमडी के बराबर, 2 दमडी 1 धेला के बराबर, 1 धेला 1.5 पाई के बराबर, 3 पाई के बराबर एक पैसा, 4 पैसे का एक आना, 16 आना का एक रूपया होता था। इस एक रूपए में अब 100 पैसे होते हैं। 18वीं शताब्दी से पहले सोने और चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। मौर्यकाल में सोने, चांदी और सीसे के सिक्कों का प्रचलन था। देश में 1949 में स्वतंत्र भारत का पहला नोट एक रूपए की मुद्रा के रूप में छापा गया। 1960 में अलग–अलग रंग की मुद्रा छापी जाने लगी और अनेक प्रकार के नोट भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा छापे जाने लगे जिनमें 2 रूपए, 5 रूपए, 10 रूपए, 20 रूपए, 50 रूपए, 100 रूपए, 500 रूपए और 1000 रूपए के नोट प्रमुख रूप से हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक रूपए विमुद्रीकरण अर्थात चलन से बाहर करने का कार्य भी नियत वैधानिक प्रक्रिया अपना कर करता है। इस प्रकार मुद्रा की विकास यात्रा का सफर फूटी कौडी–कौडी–दमडी–धेला–पाई–पैसा–आना–रूपया–क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड तक पहुँचा जो अब डिजिटल मुद्रा के रूप में पंख पसारने को आतुर है। डिजिटल मुद्रा की विकास यात्रा अभी भविष्य में इसके विकास पर निर्भर है। ऐसा माना जा रहा है कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा एवं आत्म विश्वास प्रदान करेगा।

इस तरह की मुद्रा जारी करने वाला भारत विश्व के बड़े राष्ट्रों में पहला बड़ा राष्ट्र होगा। इस मुद्रा का नाम डिजिटल रूपया (Digital Rupee) होगा। डिजिटल रूपया ग्राहकों के ऑनलाइन टोकन के रूप में जमा खातों से क्रय शक्ति को मोबाइल वॉलेट में हस्तांतरित करने की अनुमति देगा और यह देश में प्रचलित मुद्रा की भाँति भारतीय रिज़र्व बैंक की देयता होगी। एक प्रकार से यह एटीएम रहित बैंक नोट की तरह ही काम करेगा। अनेक छोटे राष्ट्रों ने भी इस तरह की मुद्रा को जारी किया हुआ है जिनमें बहामास, इस्टर्न केरिबियन के 7 राष्ट्र और नाइजीरिया प्रमुख है। नाइजीरिया की डिजिटल मुद्रा का नाम ई–नायरा है। अनेक देश भी ऐसा करने के बारे में विचार कर रहे हैं। डिजिटल मुद्रा को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के रूप में होगी। इस मुद्रा को आभासी मुद्रा के रूप में भी जाना जा सकेगा क्योंकि इसे देखा या छुआ नहीं जा सकेगा और न ही जेब या पर्स में रखा जा सकेगा अर्थात यह सरकारी गारंटी वाला बटुआ (वॉलेट) होगा। डिलिटल मुद्रा को जब चाहे कागजी मुद्रा में बदल सकते हैं। इस मुद्रा को भारतीय रिज़र्व बैंक जारी करेगा। यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी। परन्तु यह वैधानिक मुद्रा के रूप में मान्य होगी। इसका एक सार्वभौमिक पहचान होगी यानि एक मुद्रा दूसरी मुद्रा से अलग होगी। इसके माध्यम से आसानी से खरीददारी की जा सकेगी। यह मुद्रा जोखिम रहित और सुरक्षित होगी। इसका एक आंतरिक मूल्य होगा। लेकिन यह क्रिप्टो मुद्रा से एकदम अलग होगी क्योंकि इस मुद्रा को मान्यता प्राप्त होगी जबकि क्रिप्टो मुद्रा सभी देशों में मान्य नहीं है। परन्तु इस डिजिटल मुद्रा को जारी करने से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक को मौजूदा बैंकिंग अधिनियम के प्रावधानों में सुधार करना आवश्यक है क्योंकि अभी तक के बैंकिंग अधिनियम में भौतिक मुद्रा के संबंध में ही प्रावधान है। इसके लिए संसद में डिजिटल मुद्रा के बारे में कानून बनाया जाना भी आवश्यक है। इसके साथ भारतीय सिक्का अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) आदि में भी व्यापक संशोधन करना होगा।

देश के आम बजट में निजी डिजिटल मुद्रा (क्रिप्टो मुद्रा) से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत कर लगाने की चर्चा भी की गई है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अध्यक्ष जेबी महापात्रा ने बताया है कि देश में 10 (कुल 40) प्रमुख क्रिप्टो मुद्रा एक्सचेंज का कारोबार 1 लाख करोड़ रूपए से अधिक है। वर्ष 2021 में क्रिप्टो मुद्रा के कारोबार में 641 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस तरह की मुद्रा पर 15 प्रतिशत कर थाइलैंड सरकार द्वारा लगाया जाता है। यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि क्रिप्टो मुद्रा की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटेन का एक कैफे इसमें भुगतान स्वीकार करता है। यह तो मात्र शुरूआत है।

यद्यपि यह सत्य है कि वर्ष 2018–19 के बजट में यह बताया गया था कि क्रिप्टो मुद्रा को भारत में मान्यता नहीं है। इसके नियमन के लिए नवंबर 2017 में एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया। इसके सुझावों पर क्रिप्टो मुद्रा प्रतिबंध एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2019 बनाया गया। यह भी सत्य है कि क्रिप्टो मुद्रा के बारे में इस समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक को भविष्य में डिजिटल मुद्रा के बारे में सुझाव दिया गया। वर्ष 2018 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को क्रिप्टो मुद्रा में कार्य करने से रोका गया जिसे 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक निजी डिजिटल मुद्रा का विरोध करता है क्योंकि यह मुद्रा सुरक्षित नहीं है और इसमें कोई जारीकर्ता न होने के राष्ट्रीय सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करती है। ऐसा माना जाता है कि विश्व में 1500 से अधिक निजी डिजिटल मुद्राएँ प्रचलित है। देश में निजी डिजिटल मुद्रा संबंधी कोई विशेष कानून नहीं है बल्कि इस हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग के मौजूदा नियमों एवं कानूनों के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जाती है। आज विश्व में अन्य देश सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में प्रयास कर रहे हैं। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को डिजिटल मुद्रा लाने की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए। यह भविष्य की मुद्रा है और यह तकनीकी रूप से सुरक्षित है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आने से क्रिप्टो करेंसी स्वतः ही बाजार से हट जाएगी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के अनेक लाभ भी है जो इस प्रकार है–

लाभ

1. इससे नकदी पर निर्भरता कम होगी। इससे कागजी मुद्रा की छपाई, भण्डारण और परिवहन की लागतों में कमी होगी। साथ ही देश के संसाधनों की बचत भी होगी।
2. इससे कम समय में भुगतान हो सकेगा।
3. इससे कम लागत में भुगतान संभव है और भुगतान व्यवस्था अधिक पारदर्शी एवं तकनीक प्रधान होगी।
4. इस तरह की मुद्रा से अंर्तबैंक समायोजन की आवश्यकता भी नहीं होगी।
5. इससे भौतिक नकदी के उपयोग को कम किया जा सकता है जिससे बैंकों के कार्य भार में कमी होगी।
6. बैंक जमा राशि कम होगी इससे अधिक साख निर्माण होगा।
7. इससे काले धन पर अंकुश लगेगा।
8. बिना किसी बैंकिंग शुल्क के भुगतान किया सकेगा।
9. इसके माध्यम से लेनदेन करने पर व्यक्तिगत जानकारी भी सुरक्षित रहेगी और निजी क्रिप्टो मुद्रा से उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करेगी।
10. इस मुद्रा के गुम होने एवं नष्ट होने का भी भय नहीं है।
11. इस तरह की मुद्रा को प्रतिबंधित करना आसान है।
12. निजी डिजिटल मुद्रा पर रोक लगेगी।

सुझाव

डिजिटल मुद्रा के संबंध में विश्व के बड़े देशों जैसे स्वीडन, जापान, यू.एस. और यूरो देशों ने भी अभी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया है, ये देश अभी भी इन मुद्राओं की व्यवहार्यता, उपयोगिता और मूल्य पर विचार कर रहे हैं। भारत को भी इस संबंध में सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। डिजिटल मुद्रा के जारी होने पर डिजिटल भुगतान वाली समस्याएँ सामने आ सकती है जिसमें कि साइबर सुरक्षा, वायरस, हैंकिंग आदि प्रमुख है। आज भी देश में एक बड़ी मात्रा में बैंक ग्राहक व्यक्तिगत लेनदेन पर ही अधिक विश्वास रखते हैं। आज भी ऑनलाइन बैंकिंग को शक के दायरे में रखा जाता है। ऐसे ग्राहकों को डिजिटल मुद्रा के प्रयोग हेतु प्रेरित करना चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक के आदेशानुसार (11 अगस्त 2016) यदि ग्राहकों को तकनीकी कारणों से नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदार बैंक ही होगा। डिजिटल मुद्रा आने पर ऑनलाइन बैंकिंग का अधिक विस्तार होगा। इस हेतु निम्नलिखित सुझावों पर ध्यान देना चाहिए–

1. नो योर कस्टमर (KYC) के मापदंडों में कठोरता को अपनाना।
2. इस तरह की मुद्रा लागू करने से पूर्व निवेशकों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
3. जनसामान्य में निजी डिजिटल मुद्रा और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के अंतर का प्रचार–प्रसार करना चाहिए ताकि वे भी इसको समर्थन दे।
4. शीघ्र ही निजी डिजिटल मुद्रा पर कानून बनाने चाहिए। अन्यथा साइबर अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग और डाटा सुरक्षा जैसी समस्याओं में वृद्धि हो सकती है।
5. डिजिटल मुद्रा लागू करने से पूर्व देश में इंटरनेट सुविधा, मोबाइल तक पहुँच आदि पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
6. यद्यपि भारतीय बैंकों की सुरक्षा प्रणाली मजबूत एवं विश्वसनीय है फिर भी डिजिटल मुद्रा का प्रयोग करते समय सावधान एवं जागरूक रहने की आवश्यकता है।
7. यूजरनेम, पासवर्ड की सुरक्षा के व्यापक प्रयास करने चाहिए। धोखाधड़ी से बचने के लिए सशक्त कानून बनाने चाहिए।
8. कंप्यूटर एवं मोबाइल में एंटी वायरस का प्रयोग होना चाहिए।

निष्कर्ष

यह सही है कि वर्तमान 21वीं शताब्दी सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल तकनीक को महत्व देती है। विश्व के अनेक देशों में डिजिटल मुद्रा प्रयोग में ली जाने लगी है। डिजिटल मुद्रा के प्रयोग से अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। अभी कागजी मुद्रा जारी करने में 100 रूपए के एक नोट के प्रकाशन एवं चलन में लाने के लिए 15–17 रूपए का खर्च आता है इससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है, डिजिटल मुद्रा से इससे बचा जा सकता है। इस हेतु नागरिकों को डिजिटलीकरण के बारे में जागरूक करना होगा और बैंकों एवं सरकार को डिजिटल साक्षरता शिविरों का आयोजन करना चाहिए। देश में तकनीकी संसाधनों का विकास करना होगा। तभी हम इस डिजिटल मुद्रा को आसानी से संचालित कर सकेंगे। अभी यह भविष्य के गर्भ में है कि डिजिटल मुद्रा के बाद परिस्थितियाँ कैसी होगी?

संदर्भ

1. गुप्ता अजय, 1 फरवरी 2022, नॉलेजमेपस डॉट ओआरजी
2. नीरज सिंह, भास्कर एक्सप्लेनर, 3 फरवरी 2022
3. चतुर्वेदी दीपक, बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, 30 नवंबर 2021
4. डेली अपडेट, दृष्टि, 23 जुलाई 2021
5. एडिटोरियल, दृष्टि, 10 फरवरी 2022
6. दैनिक नवज्योति, नागौर, 8 फरवरी 2022
7. चावला मेघा, 5 दिसंबर 2016, आजतक डॉट इन
8. गोरा ईशान, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 19 दिसंबर 2021
9. चौधरी ज्योति, पंजाब केसरी, 23 अक्टूबर 2021